राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 2016/2018

1. सुश्री अश्विनी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती भंवरी देवी, ए.एन.एम, जाति - नट, ग्राम- बोरुंदा, तहसील- पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

2. साहिल पेमावत पुत्र स्वर्गीय श्रीमती भंवरी देवी, ए.एन.एम, जाति - नट, ग्राम- बोरुंदा, तहसील- पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर।

3. सुश्री सुहानी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती भंवरी देवी, ए.एन.एम, अपने प्राकृतिक संरक्षक दादी- श्रीमती पुनी देवी पत्नी -स्वर्गीय श्री उदाराम, आयु- लगभग 75 वर्ष, जाति - नट, ग्राम- बोरुंदा, तहसील- पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर के माध्यम से।-----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान राज्य, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य, भवन, जयपुर।

3. मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

4. उप निदेशक, राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग, बीमा भवन, कचहरी परिसर, जोधपुर।

5. संयुक्त निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, जोधपुर।
6. भारतीय जीवन बीमा निगम, मंडल कार्यालय, 1 सेंट वेस्ट पटेल नगर, सर्किट हाउस रोड, जोधपुर अपने विपणन प्रबंधक के माध्यम से।

7. श्री अमरचंद पुत्र स्वर्गीय श्री उदाराम, जाति - नट, ग्राम- बोरुंदा, तहसील- पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर। (वर्तमान में केंद्रीय कारागार, जोधपुर में स्थित है।)

8. तहसीलदार, पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर----उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री यशपाल खिलेरी

उत्तरदाताओं के लिए:- सुश्री वंदना भंसाली, ए. जी. सी.

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

12/01/2024

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (ए. एन. एम.) के रूप में सेवा करते हुए उनकी माँ की मृत्यु के कारण उत्तरदाताओं द्वारा सेवा लाभों से इनकार करने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की दिवंगत माँ श्रीमती भंवरी देवी की वास्तव में, दुखद हत्या कर दी गई थी, जैसा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा जांच के दौरान सामने आया था। नतीजतन, प्रतिवादी चिकित्सा विभाग द्वारा सरकारी सेवा से उनका नाम हटा दिया गया।

2. अनावश्यक विवरणों से रहित संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है:- याचिकाकर्ताओं की मां श्रीमती भंवरी देवी, प्रतिवादी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ए. एन. एम. के रूप में कार्यरत थीं। 1 सितंबर, 2011 को, वह अपनी बेची गई कार के भुगतान लेने के लिए बिलाड़ा गई, लेकिन कभी घर वापस नहीं लौटी, जिससे उनके पति अमरचंद को लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद, 5 सितंबर, 2011 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें सोहन लाल बिश्नोई नामक व्यक्ति को उसके लापता होने में

शामिल किया गया। आगामी सी. बी. आई. जांच में आरोपी सोहन लाल बिश्नोई और सह-आरोपी अमरचंद (याचिकाकर्ताओं के पिता) के हाथों उनकी दुखद मृत्यु का पता चला, जिसके कारण 1 सितंबर, 2011 को सरकारी सेवा सूची से उनका नाम हटा दिया गया। मृत सरकारी सेवा नियमों, 1996 के आश्रितों की राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 2 को 28 फरवरी, 2012 को एल. डी. सी. के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को अपनी माँ के अपने हकदार सेवा लाभों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्रत्यर्थी चिकित्सा विभाग ने श्रीमती भंवरी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसे पीपाड़ सिटी के तहसीलदार ने अस्वीकार कर दिया था, के जमा करने पर सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की शर्त रखी। इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी संख्या 7 ने 2017 में अपनी पत्नी श्रीमती भंवरी देवी के नॉमिनी के रूप में पारिवारिक पेंशन और अन्य लाभों के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे भी मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में संसाधित नहीं किया गया था।

4. रिट याचिका के जवाब में, प्रतिवादियों का रुख यह है कि अमरचंद श्रीमती भंवरी देवी के पति हैं। राज्य बीमा, भविष्य निधि लाभ और पेंशन के लिए पात्र नामांकित व्यक्ति हैं। हालाँकि, चूंकि अमरचंद कोई भी दावा प्रस्तुत करने में या आवश्यक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, इसलिए पात्रता का दावा नहीं किया गया है। राज्य बीमा और भविष्य निधि विभाग के उत्तरदाता संख्या 4 ने उत्तरदाता संख्या 1 से 3 द्वारा किए गए अभिकथन को दोहराया।

5. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, मैं आगामी पैराग्राफ में अपने विचार-विमर्श और निष्कर्षों को स्पष्ट करते हुए मुद्दों को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

6. पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 (संक्षेप में, 1996 के नियम) के नियम 66 और 67 के लिए रखा जा सकता है, जिन्हें तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः-

"नियम 66. परिभाषाएँ:-

(1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए 'परिवार' में सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित संबंध शामिल होंगेः-(ए) महिला सरकारी कर्मचारी के मामले में पुरुष सरकारी कर्मचारी और पति के मामले में पत्नी; (बी) न्यायिक रूप से अलग पत्नी या पति, व्यभिचार के आधार पर ऐसा अलगाव नहीं दिया जा रहा है; (सी) विधवाओं/तलाकशुदा बेटी सहित बेटे/बेटी को 25 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक या 6,000 रुपये से अधिक मासिक आय अर्जित करने पर या उसकी शादी/पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो। बेटा/बेटी शब्द में कानूनी रूप से गोद लिया गया बेटा/बेटी और सरकारी कर्मचारी की मरणोपरांत संतान भी शामिल होगी। (घ) वे माता-पिता जो जीवित रहते हुए पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी ने न तो कोई विधवा छोड़ी हो और न ही कोई बच्चा और माता-पिता की आय 6,000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो।

(2) 'परिलब्धि' से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 45 में परिभाषित परिलब्धि अभिप्रेत है, जिसे मृतक

सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए या अपनी सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले अपनी मृत्यु की तारीख को प्राप्त कर रहा था; यदि सेवा में रहते हुए या अपनी सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले अपनी मृत्यु की तारीख को ऐसा सरकारी कर्मचारी छुट्टी (असाधारण छुट्टी सहित) या निलंबन पर कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है, तो परिलब्धि का अर्थ है वे परिलब्धि जो उसने ऐसी छुट्टी या निलंबन पर आगे बढ़ने से तुरंत पहले प्राप्त की थी।

नियम 67. अनुदान की शर्त

पारिवारिक पेंशन के लिए स्वीकार्य होगी-(क) एक विधवा/विधुर, मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख तक, जो भी पहले हो; (ख) अविवाहित पुत्र जब तक 25 वर्ष का नहीं हो जाता या उसकी मासिक आय 6,000/- रुपये से अधिक हो जाती है, जो भी पहले हो। (ग) अविवाहित बेटी, चाहे उसकी शादी की तारीख तक हो या मासिक आय जो भी पहले हो, उससे अधिक हो। (घ) किसी भी उम्र की विधवा/तलाकशुदा बेटी, जो पुनर्विवाह की तारीख तक हो या जिस तारीख से वह मासिक आय से अधिक करना शुरू करती है, जो भी पहले हो, प्रति माह या मृत्यु की तारीख तक। (ङ) ऐसे माता-पिता जो जीवित रहने के दौरान पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी पर निर्भर थे, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी ने न तो कोई विधवा छोड़ी हो और न ही कोई बच्चा और न ही माता-पिता की आय। (ii) ऐसे किसी भी बेटे या बेटी को आजीवन पारिवारिक पेंशन की अनुमति देने से पहले, मंजूरी देने वाला प्राधिकारी यह संतुष्ट करेगा कि विकलांगता ऐसी प्रकृति की है ताकि उसे आजीविका कमाने से रोका जा सके, जिसका

प्रमाण मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा न्यायविद के पद से नीचे के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र द्वारा दिया गया है, जिसमें यथासंभव, सटीक मानसिक या शारीरिक अक्षमता का उल्लेख किया गया है। और (iii) ऐसे बेटे या बेटी या ऐसे बेटे या बेटी के प्राकृतिक/कानूनी अभिभावक के रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जो अभिभावक के माध्यम से पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, हर तीन साल में एक चिकित्सा अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी/चिकित्सा न्यायविद के पद से कम नहीं है, इस प्रभाव से कि वह विकार या मानसिक अक्षमता से पीड़ित है या शारीरिक रूप से विकलांग या विकलांग या अंधा या बहिरा और गूंगा बना हुआ है।

6. उपरोक्त नियमों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एक विधवा/तलाकशुदा बेटी सहित बेटे और बेटी, जब तक कि वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं या अन्यथा 6,000/- रुपये से अधिक मासिक आय अर्जित करते हैं, एक कर्मचारी की मृत्यु पर सेवा लाभ के हकदार हैं।

7. उत्तरदाताओं के आचरण से स्पष्ट होने वाला एकमात्र तर्क, जो लाभ प्रदान करने में बाधा के रूप में कार्य करता था, ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक माँ द्वारा अपने पति का नाम अपने सेवा रिकॉर्ड में सेवा लाभों के लिए लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया था।

8. अपनी पत्नी की हत्या के मुकदमे में स्वयं सह-अभियुक्त/विचाराधीन होने के कारण, नाबालिगों के पिता किसी भी लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य हो गए हैं। इस आधार पर,

इक्विटी को संतुलित करने और याचिकाकर्ताओं की मां की मृत्यु से उत्पन्न आरोपी पिता के किसी भी संभावित अन्यायपूर्ण संवर्धन को रोकने के लिए, उत्तरदाताओं को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के स्वीकार्य अनुपात में उनकी मृत्यु से उत्पन्न सभी सेवा लाभों का पता लगाने का निर्देश दिया जाता है।

9. निर्धारण के पश्चात, पिता के हिस्से के अनुरूप एक राशि को रोक दिया जाएगा, जबकि शेष राशि उस तारीख से पूर्वव्यापी रूप से वितरित की जाएगी, जब यह सामान्य रूप से नाबालिगों को वितरित की जाती, अगर उनके पिता को हत्या में शामिल नहीं किया जाता।

10. कहने की जरूरत नहीं है कि पिता के बरी होने की स्थिति में, उसे कानून के अनुसार अपना हकदार देय राशि प्राप्त होगी।

11. उपार्जित बकाया, विधिवत गणना और लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज के साथ चार महीने की अवधि के भीतर वितरित किया जाना चाहिए।

12. विभाग को मृतक मां के मृत्यु प्रमाण पत्र के निरीक्षण का अनुरोध करने या आपराधिक अदालत से इसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस तरह के आवेदन को दायर किए जाने पर, विद्वत विचारण न्यायालय से अनुरोध किया जाता है कि वह विभाग के प्रतिनिधि को मृत्यु प्रमाण पत्र का निरीक्षण करने और/या उसकी प्रति प्रदान करने की अनुमति दे।

13. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।